problems and to the need of heart operations of children in Andhra. Pradesh.

Sir, there is a very serious societ and health concern in Andhra. Pradesh. Thousands of...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Hanumantha Plao, what you are reading is not in the text here. ...(Interruptions)... You have to read only the text that you have given to the hon. Chairman.

SHRI V. HANUMANTHA RAO: All right, Sir. Each operation costs about...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You start from 'The State Government does not have...'. You have to read what you have given to the Chairman. ... (Interruptions)...

SHRI V. HANUMANTHA RAO: The State Government does not have the resources to fund the critical heart operations of children who are waiting for months for heart operations. Many children are also dying while they wait for heart operations in Andhra Pradesh. I request the Central Government to pay attention to this critical problem as parents are agitating for medical help.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all.

SHRI V. HANUMANTHA RAO: That's all?

भी उपस्थापि: इतना ही अप्रूच हुआ है।...(व्यववाप)...

SHRI V. HANUMANTHA RAO: No, Sir. I want to say something. What is this, Sir? I want the Central Government to intervene in this matter. There is no money in Andhra Pradesh. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY OHAIPMAN: Shri Kripal Parmer.

Demand to make it mandatory to print Posticide contents on Cold Det ... Bottles

श्री कृष्याल परमार (हिमाचल प्रवेश): महोचब, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना बाहता हूं कि देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विक्रय किए जा रहे शीतल पेयों (कोल्ड ब्रिंक्स) में मानक से 50 प्रतिशत अधिक जहरीले रसायन और कीटनाशकों का पाया जाना विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र, सेंटर फाए साइंस एंड एनवायरन्मेंट (सीएसई) की प्रदूषण निगरानी प्रयोगशाला की एक टीम ने व्यवस्तरीय मान्य जांच प्रक्रियाओं के अनुसार जांच करने पर

ब्रमाणित किया था। तरकार ने इससे बितित होकर एक संयुक्त तंसदीय जांच समिति (जेपीसी) का गठन किया था।

तंसक्षेत्र जांच समिति ने दो वर्ष तक विमिन्न बहुराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कम्पनियों के प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के साक्ष्य लेकर सर्वसम्मति से अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्कृत किया। वह प्रतिवेदन भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के शीतल येवों में स्वीकृत मापदंडों से अधिक जहरीले स्सायनों एवं कीटनाशकों की उपस्थिति को प्रमाणित करता था और कुल मिलाकर जांच प्रतिवेदन उक्त कम्पनियों के प्रतिकृत था।

में आषके माध्यम से सरकार से निवेदन करना बाहता हूं कि जिस प्रकार से लिगरेट के पैकेट एवं शराब की बोतलों पर चेतावनी छापी जाती है कि "इमका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" उसी प्रकार बहुराष्ट्रीय कन्यनियो द्वारा देश में बिक्रम किए जा रहे शीतल पेय की बोतलों पर चेतावनी छापा जाना अनिवार्य किया जाए कि "इसमें जहरीले रसाबन और कीटनाशी हैं।"

श्री मनोज भट्टाकार्य (पश्चिमी बंगाल) : सर, मैं माननीब सदस्य से स्वबं को संबद्ध करता हूं।

श्रीनती सविता शारबा (गुजरात) : महोदय, मैं मानमीय सबस्य से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री अनय मारू (भारखंड) : नहोदय; मैं माननीय सदस्य से त्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश) : महोदय, इसी तरह से पैक्ड जूसिज पर भी लिखा होना चाहिए। ...(व्यवधान)... बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं। ...(व्यवधान)... जूस आप नहीं बना रहे। आप क्वों परेशान हो रहे हैं? इसमें कोई बिरोध नहीं है। समर्थन ही कर रहा हूं, क्यों घबरा रहे हैं?

Need for retaining original plan of Rs.19.00 crores under PMGSY for Andhra Pradesh

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, as my Special Mention relates to the poor rural people of Andhra Pradesh, I draw the attention of the Government of India through this Special Mention. The Government of Andhra Pradesh has been informed that the allocation for Prime Minister's *Grameen Sadak Yojana*, Phase IV for Andhra Pradesh will now be only Rs.90 crores as against the annual allocation of Rs.190 crores. It is injustice to Andhra Pradesh.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please confine to your text.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, Andhra Pradesh is predominantly a rural State with 72.65 per cent of the population living in the rural areas. Out of 67505 habitants, 53986 are connected with roads and 13519 do not